semi-skilled and unskilled workers. The services sector such as general administration, education, health and family planning are also expected to provide considerable employment opportunities to teachers and doctors and para-medical personnel.

For certain categories of highly educated persons like engineers and technicians, special measures for meeting the situation have been initiated.

In the budget for 1970-71, special effort has been made to make the Plan more employment-oriented by providing for a total Plan outlay of Rs. 480 crores higher than the Plan outlay 1969-70. Along with this significant increase in the level of outlays, there is also specific reorientation in many of the new schemes proposed to be implemented for generating more employment.

Steps are also being taken to strengthen the career advice and vocational guidance services in Universities and Schools to channalise the youth into productive employment/self-employment. Simultaneously, a programme for training-in industry and reorientation of existing training programmes is envisaged with a view to making the educated unemployed (particularly the engineers and craftsmen) better equipped for self-employment and employment.

जूट मिल कर्मचारियों द्वारा हड़ताल करने की धमकी

2405. **श्री बाल्मीकि चौधरी :**
श्री रवि राय :

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जूट मिलों के कर्मचारियों ने हड़ताल करने की धमकी दी है;

(ख) यदि हां, तो उनकी मांगों की मुख्य रूपरेखा क्या है; और

(ग) इस हड़ताल को रोकने के लिये सरकार द्वारा क्या कारगर कार्यवाही की जा रही है ?

श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) से (ग). जी हां, प्राप्त सूचना के अनुसार श्रमिकों ने 7 दिसम्बर, 1970 से अनिश्चित काल के लिए हड़ताल पर जाने का नोटिस दिया है। उनकी मांगें मुख्यतः ग्रेच्युटी, न्यूनतम वार्षिक बोनस, बंद की गई मिलों को दोबारा चालू करने, कर्मचारी राज्य बीमा योजना के परिचालन से संबंधित शिकायतों, बदली श्रमिकों के लिए निर्वाह भत्ते, आवास भत्ते, छुट्टियों और त्योहारी छुट्टियों में वृद्धि और अगस्त 1969 में हड़ताल की समयावधि के लिए मजदूरी से संबंधित हैं। बताया गया है कि राज्य श्रम आयुक्त ने 24 नवम्बर 1970 को पक्षों से इस विषय पर विचार विमर्श करने के लिए एक त्रिपक्षीय बैठक बुलाई है।

Number of Development Blocks in the Country

2406. SHRI J. H. PATEL : Will the Minister of FOOD AND AGRICULTURE be pleased to state the number of development blocks at present in the country, State-wise ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FOOD, AGRICULTURE, COMMUNITY DEVELOPMENT AND COOPERATION (SHRI S. C. JAMIR) : The information is available in the Annual Report of the Department of Community Development for 1969-70 ?

राजस्थान में पलाना कोयला खान का बंद होना

2407. **श्री प० ला० बारूपाल** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री राजस्थान में पलाना कोयला खान बंद होने के बारे में 22 दिसम्बर, 1969 के तारांकित प्रश्न संख्या 4842 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केंद्रीय सरकार की खान सुरक्षा विभाग की राजस्थान में पलाना कोयला खान में लगी आग के कारण से संबंधित प्रतिवेदन का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या पलाना खान मजदूरों में खान